



प्रत्युष नवबिहार

रांची संस्करण

www.tezraftarlive.com
Email-navbiharjh@gmail.com

रांची, पटना और दिल्ली से प्रकाशित



रांची • गुरुवार • 03.10.2024 • वर्ष : 15 • अंक : 74 • पृष्ठ : 12 • आगंत्रण मूल्य : ₹ 2 रुपया



तमाम अड़चनों को दूर कर हेमन्त सरकार
ने कराया कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण



योजना लागत

₹224.94 करोड़

फ्लाईओवर की लम्बाई

2240 मीटर

फ्लाईओवर की चौड़ाई

16.6 मीटर

₹3264.00 करोड़
की 31 परियोजनाओं का
शिलान्यास एवं उद्घाटन

शिलान्यास की जाने वाली
27 योजनाओं की कुल लागत
₹2471.90 करोड़

उद्घाटन की जाने वाली 04
योजनाओं की कुल लागत
₹792.10 करोड़

कांटाटोली फ्लाईओवर, बिरसा
चौक-धूर्वा गोल चक्कर 4 लेन
स्मार्ट पथ एवं कांको चौक-विनोद
बिहारी चौक-गोल बिल्डिंग 8-लेन
पथ (धनबाद) का उद्घाटन

सिरमटोली-कांटाटोली कनेक्टिंग
फ्लाईओवर एवं सहजानन्द
चौक-कांको दोड फ्लाईओवर का
शिलान्यास

मुख्य अतिथि
श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

श्री संजय सेठमाननीय केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री-सह-सांसद,
रांची लोकसभा**श्री हफीजुल हसन**माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास,
अल्पसंस्कृत कल्याण, निर्बंधन विभाग**श्रीमती महुआ माझी**

माननीय सांसद, राज्यसभा

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह

माननीय विधायक, रांची

दिनांक : 04 अक्टूबर 2024 | समय: पूर्वाह्न 11:30 बजे

स्थान : संत पॉल कैथेड्रल मैदान, बहु बाजार के निकट, रांची

उद्घाटन

- कांको चौक-विनोद बिहारी चौक-गोल बिल्डिंग 8-लेन पथ, कुल लागत ₹461.90 करोड़
- अनगड़ा-हाहे-राहे पथ (MDR-021) (लम्बाई -26. 687 KM) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य, कुल लागत ₹57.95 करोड़
- बिरसा चौक से धूर्वा गोल चक्कर (लम्बाई-2.60 KM) का चार लेन में मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (साईफिल ट्रैक एवं फुटपाथ सहित) एवं धूर्वा गोल चक्कर से प्रोजेक्ट बिल्डिंग (लम्बाई-1.50 KM) पथ का राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य (लम्बाई-4.10 KM), कुल लागत ₹47.33 करोड़

शिलान्यास

- सहजानन्द चौक के नजदीक से जज कॉलोनी के नजदीक 04 लेन एलिवेटेड पथ का निर्माण कार्य, कुल लागत ₹430.75 करोड़
- गोला-मुरी पथ का 4-लेन निर्माण कार्य, कुल लागत ₹333.17 करोड़
- धनबाद जिला अंतर्गत मटकुरिया फ्लाईओवर का निर्माण, कुल लागत ₹256.54 करोड़
- Foundation stone laying of fly over from Bahu Bazar to Patel Chowk Connecting Siramtoli Chowk and Kokar Bahu Bazar (Length 1.25 KM) in Ranchi city, कुल लागत ₹213.35 करोड़
- भुईयाडीह लिटी चौक से भिलाई पहाड़ी पथ में स्वर्णरेखा नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण, कुल लागत ₹77.77 करोड़
- अन्य 19 पथों/ROB का निर्माण कार्य, कुल लागत ₹713.49 करोड़



प्रत्युष नवविहार

रांची संस्करण

www.tezraftarlive.com
Email-navbiharjh@gmail.com

रांची • गुरुवार • 03.10.2024 • वर्ष : 15 • अंक : 74 • पृष्ठ : 12 • आमंत्रण भूल्य : 2 रुपये

पीएम ने हजारीबाग में 80,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया

जनजातीय संस्कृति को संजोने वाले ज्ञारखंड से उनका और भाजपा का दिल का रिता : मोदी



► लगभग 550 जिलों के 63,000 आदिवासी गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया।

► 40 एकलत्व विद्यालयों का उद्घाटन किया और 25 एकलत्व विद्यालयों की आधारशिला भी रखी।



आधारभूत संरचना का हो दहा विकास अखुआ आभार हेमन्त सरकार

ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 सुकुरहुट का उद्घाटन एवं फेज- II का भूमि पूजन



ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 की विवरणी:

- योजना लागत ₹113.24 करोड़
- कुल क्षेत्रफल 40.68 एकड़
- निर्माण अवधि 24 माह
- अधिकतम 22 मीटर लम्बाई वाले भारी मालवाहक वाहनों हेतु 424 पार्किंग
- 3400 एवं 6100 वर्गमीटर का वेयरहाउस
- 120 टन क्षमता के दो धर्मकांता
- मालवाहक वाहनों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु सर्विस स्टेशन इत्यादि

मुख्य अतिथि

श्री हेमन्त सोरेन

माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

८८७

गणिमामयी उपस्थिति

श्री संजय सेठ

माननीय केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद, रांची लोकसभा

श्री हफीजुल हसन

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास, संसाद, रांची लोकसभा

ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 की विवरणी:

- योजना लागत ₹57.82 करोड़
- कुल क्षेत्रफल 9.12 एकड़
- निर्माण अवधि 18 माह
- अधिकतम 14 मीटर लम्बाई वाले भारी मालवाहक वाहनों हेतु 256 पार्किंग
- G-3 इंटीग्रेटेड बिल्डिंग
- मालवाहक वाहनों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु सर्विस स्टेशन इत्यादि

श्रीमती महुआ माझी

माननीय सांसद, साच्चासभा

श्री समरी लाल

माननीय विधायक, कोके

दिनांक 03 अक्टूबर 2024

समय: मध्याह्न 12:00 बजे

स्थान: सुकुरहुट ITBP कैप के निकट, रिंग रोड, रांची

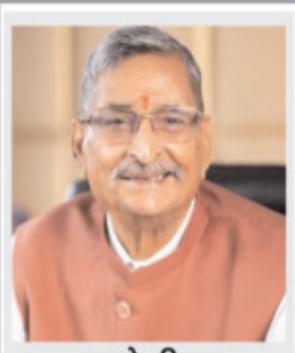


टीपीसी ने ली हजारीबाग के केरेडारी में हाइवा में आगजनी की जिम्मेदारी



हजारीबाग : जिले के केरेडारी में सोमवार की देर रात पांच हाइवा को आग के हावाले कर दिया गया था। ये सभी हाइवा कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगी थीं। इसको टीपीसी उग्रवादी संघटन ने बुधवार को इस घटना का जिम्मा लिया है। साथ ही बीकेएस त्रिपायी गुप्त के उस दावे का खंडन भी किया, जिसमें आगजनी की जिम्मेदारी ली गई थी। टीपीसी ने कहा है कि हमारे संगठन की बात नहीं मनाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीपीसी ने कहा है कि बड़कापाव, केरेडारी और टेंडवा माईस क्षेत्र में चल रहे तमाम कोयला कंपनियों और अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आप कोयला का काम कर रहे हैं। आप हमारे संगठन से बात करके काम नहीं करती है तब तक आप लेग गाड़ी रोड में नहीं चलाएं, नहीं तो जो नुकसान होगा इसके जिम्मेदार आप खुद होगे।

इसलिए जरुरी है 'एक देश, एक चुनाव' का विचार



आर.के. सिंह

क्या बाकी देशों में भी 'एक देश, एक चुनाव' वाली व्यवस्था लागू है? अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि में 'एक देश, एक चुनाव' वाली स्थिति है। अमेरिका में हर घार साल में एक निश्चित

तारीख को ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। भारत की ही

तरह फ्रांस में संसद का नियमासन यानी नेशनल असेंबली है। वहां नेशनल असेंबली के साथ ही संघीय सरकार के प्रमुख राष्ट्रपति के साथ ही राष्ट्रीय के प्रमुख और प्रतिनिधियों का चुनाव हर पांच साल में एक साथ कराया जाता है।

प्रतिनिधियों का चुनाव हर

पांच साल में एक साथ कराया जाता है।

'एक देश, एक चुनाव' का सपना अब तो साकार सरकार ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। भलव यह कि अब देश में 'एक देश, एक चुनाव' की रास का सारा व्यवधान सारा सम्प्रेस दूर हो गया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक वक्तव्य में साफ किया था कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का यह सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। जैसे कि आपको जात ही होगा कि केंद्र सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 'एक देश, एक चुनाव' पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रामनाथ कोविंद की रिपोर्टोरी दी गई थी कि वह देश में एक सारा चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे। अब कमटी की सिफारिशों पर देश की सभी गजनीतिक मंचों पर इस पर चर्चा की जाएगी। सभी नौजवानों, कारोबारियों, पत्रकारों समेत सभी संस्थानों से इस पर चर्चा होगी। इसके बाद इसे लागू करने के लिए युप बनाया जाएगा। फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव की वक्तव्यता की थी। उक्ता कहना था कि देश में बार-बार चुनाव से विकास कार्यमें बाया आती है। किसी भी चुनाव की घोषणा होते ही अतिम रिजल्ट नहीं अनेक को नया चुनाव के लिए बार-बार चुनाव से विकास कार्यमें बाया आती है। उक्तोंने देश के सभी गजनीतिक दलों से भी आग्रह किया था कि 'एक देश, एक चुनाव' के लिए देश को अप्रीति के लिए इस दिशा में आगे आया होगा। उक्तोंने देश के सभी गजनीतिक दलों से भी आग्रह किया था कि एक देश, एक चुनाव के लिए देश को अप्रीति के लिए इस दिशा में आगे आये बढ़े। वहां तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले भाषण ने इस अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था।

बेशक, एक साथ चुनाव राखने से चुनाव प्रक्रिया की चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, क्योंकि कई चुनावों के लिए बार-बार तैयारी और कार्यालयन करने की आवश्यकता नहीं होगी। व्या आपको पता है कि कुछ माह पहले देश में हुए लोकसभा चुनाव में भी खर्च हुआ?

2024 के लोकसभा चुनाव पर 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कीरीब बाहुना से भी ज्यादा खर्च हुआ।

चुनावी खर्च पर रिपोर्ट जारी करने वाली गैर लोकार्पारी



संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने अनुमान लगाया है कि

इस बार लोकसभा चुनाव में कीरीब 1.35 लाख करोड़ रुपये खर्च 55 से 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस तह देखा जाता है कि एक देश, एक चुनाव के लिए देश की प्रीति के लिए इस दिशा में आगे आये बढ़े। वहां तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में करोड़ 1.20 लाख करोड़ रुपये ही खर्च किए थे। व्या आपको पता है कि 1951-52 में भारत के लिए चुनाव के दौरान महज 10.5 करोड़ रुपये था? चुनाव खर्च का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया प्रचार पर खर्च किया जाता है। भारतीय राजनेता मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए असाधारण और नए-नए तरीके अपना रहे हैं।

वह सबको पता है कि देश में बार-बार चुनाव होने से जनता और सरकारी अधिकारियों का समय और संसाधन बांद होता है। एक

साथ चुनाव होने से राजनीतिक स्थिता में सुधार आया।

क्वांक, सकार को बार-बार चुनावों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही एक साथ चुनाव होने से प्रशासन पर भी काम का दबाव कम होगा और वे अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 'एक देश, एक चुनाव' से कई मसलों का हल हो जाएगा। चुनावी की अवधि कम हो जाने से, शासन और विकास कार्यकालीन पर ध्यान बेहत ढंग से केंद्रित किया जा सकेगा। यह जाना जरूरी है कि भारत जैसे नेशनल असेंबली के साथ ही एक साथ चुनाव होने से प्रामुख राष्ट्रपति की साथ ही गजनीतीक भूमिका और प्रतिनिधियों का चुनाव होने पर चार साल में एक साथ कराया जाता है। स्वीडन की संसद और स्थानीय सरकार के चुनाव हर चार साल में एक साथ होते हैं। वहां तक कि नगरपालिका के चुनाव भी इन्हीं चुनावों के साथ होते हैं। वैसे तो कनाडा में हाउस ऑफ कॉमिस के चुनाव हर चार साल में कराए जाते हैं, जिसके साथ कुछ ही प्रातं स्थानीय चुनाव की संधीय चुनाव के साथ होते हैं। वैसे तो कनाडा में नए अधिकारियों का हल हो जाएगा।

चुनावी की अवधि कम हो जाने से, शासन और विकास कार्यकालीन पर ध्यान बेहत ढंग से केंद्रित किया जा सकेगा।

यह जाना जरूरी है कि भारत जैसे नेशनल असेंबली के साथ ही एक साथ चुनाव होने से प्रामुख राष्ट्रपति की साथ ही गजनीतीक भूमिका और प्रतिनिधियों का चुनाव होते हैं। वैसे तो कनाडा में हाउस ऑफ कॉमिस के चुनाव हर चार साल में कराए जाते हैं, जिसके साथ कुछ ही प्रातं स्थानीय चुनाव की संधीय चुनाव के साथ होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जैसे देश के लिए 'एक देश, एक चुनाव' का विचार बहुत ही उत्त्यक और आदर्श है। पर दिक्कत यह है कि हमारे विषयी दल इन्हें शानदार विचार की बिंबा सोचे साझे गजनीतिक स्थानीय साधने के चक्रवर्ती में निश्चिन्ता करने वाले अंत में सरकार का ही साथ हो रहे थे। उसके बाद साल 1957, 1962 और 1967 में भी

लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही हुए थे। वह मिलिसिला पहली बार उस वक्त दूरी जा चक्र के केरल में साल 1957 के चुनाव में ईमान नवदूरीवाद और प्रधानमंत्री ईदरा गाँधी ने मनमाने द्वारा से राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके अलावा साल 1972 में होनेवाले लोकसभा चुनाव भी समय से पहले कराए गए थे। साल 1967 के चुनावों में कारिग्र

सभा और विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब,

पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे गजनीतीक दलों या गठबंधन की सरकार बनी थी। इनमें से कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं और विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गई। वैसे वह बात भी है कि अगर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इसके लिए मौजूदा सख्त तौलना गुना ज्यादा इंवेण्टरी को जलूत पड़ेगी। लैसेन, वह तो ही हो जाएगा।

व्या बाकी देशों में भी 'एक देश, एक चुनाव' वाली व्यवस्था लागू है? अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि में 'एक देश, एक चुनाव' वाली स्थिति है। अमेरिका में हर चार साल में एक निश्चित तारीख को ही हो जाएगा। जैसे व्या बात भी है कि अगर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इसके लिए मौजूदा सख्त तौलना गुना ज्यादा इंवेण्टरी को जलूत पड़ेगी। लैसेन, वह तो ही हो जाएगा।

व्या बाकी देशों में भी 'एक देश, एक चुनाव' वाली व्यवस्था लागू है? अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि में 'एक देश, एक चुनाव' वाली स्थिति है। अमेरिका में हर चार साल में एक निश्चित तारीख को ही हो जाएगा। जैसे व्या बात भी है कि अगर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इसके लिए मौजूदा सख्त तौलना गुना ज्यादा इंवेण्टरी को जलूत पड़ेगी। लैसेन, वह तो ही हो जाएगा।

व्या बाकी देशों में भी 'एक देश, एक चुनाव' वाली व्यवस्था लागू है? अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि में 'एक देश, एक चुनाव' वाली स्थिति है। अमेरिका में हर चार साल में एक निश्चित तारीख को ही हो जाएगा। जैसे व्या बात भी है कि अगर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इसके लिए मौजूदा सख्त तौलना गुना ज्यादा इंवेण्टरी को जलूत पड़ेगी। लैसेन, वह तो ही हो जाएगा।

व्या बाकी देशों में भी 'एक देश, एक चुनाव' वाली व्यवस्था लागू है? अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि में 'एक देश, एक चुनाव' वाली स्थिति है। अमेरिका में हर चार साल में एक निश्चित तारीख को ही हो जाएगा। जैसे व्या बात भी है कि अगर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इसके लिए मौजूदा सख्त तौलना गुना ज्यादा इंवेण्टरी को जलूत पड़ेगी। लैसेन, वह तो ही हो

